www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 316 | जौनपुर मंगलवार, 07 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

कलीघाट तृणमूल ने रैली की अनुमति के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

कोलकाता, (एजेंसी)। कोलकाता के कालीघाट क्षेत्र की तृणमूल कांग्रेस इकाई ने प्रस्तावित रैली की अनुमति नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि पुलिस बुधवार को प्रस्तावित रैली की अनुमति नहीं दे रही है। हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि बुधवार को आयोजित होने वाली इस रैली में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह रैली बारुईपुर की घटना के विरोध में निकाली जाएगी या किसी अन्य मुद्दे पर। इससे पहले सोमवार को बारुईपुर की घटना के विरोध में ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास से मोमबत्ती मार्च निकाला था। आरोप है कि केंद्रीय बलों ने उनके जुलूस को गली के मुहाने पर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ बैरिकेड पार कर हरिश चटर्जी स्ट्रीट तक पहुंच गई थीं। उसी दिन राज्यसभा सांसद डोला सेन, प्रतिमा मंडल और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बिमान बनर्जी भी बारुईपुर पहुंचे थे। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष तृणमूल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस रैली की अनुमति नहीं दे रही है।

राम मंदिर ट्रस्ट पर महुआ मोइत्रा का निशाना

कोलकाता, (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो संदेश में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिन लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, उन्हें जवाब मिलना चाहिए। मोइत्रा ने कहा कि फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में इस ट्रस्ट की घोषणा की थी और इसके बाद गृह मंत्रालय ने 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ट्रस्ट का गठन सरकार की अधिसूचना के माध्यम से हुआ और इसका संचालन आम जनता के दान से होता है, तो इसे निजी ट्रस्ट बताकर सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर क्यों रखा गया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 में ट्रस्ट की जानकारी मांगने पर आरटीआई आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह निजी ट्रस्ट है। बाद में केंद्रीय सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा गया ।

भारत और इंडोनेशिया की रणनीतिक साझेदारी का शुरू होगा नया स्वर्णिम अध्याय - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई गहराई आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी अब नई उड़ान भर रही है और दोनों देश विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आज से दोनों देशों की साझेदारी का एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव

पूरी दुनिया और मानवता पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए जाने पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, वहां की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों, भारत–इंडोनेशिया की ऐतिहासिक मित्रता और दोनों देशों के लोगों के स्नेह का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा आदान–प्रदान, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। साथ ही दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह विकास और समुद्री व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए गरीबी उन्मूलन और नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिड–डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुभव साझा किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए समझौते से इंडोनेशिया के लोगों को भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती दवाएं आसानी से मिल सकेंगी।

वक्फ की लूट पर कभी नहीं बोले : योगी आदित्यनाथ

प्रतापगढ़, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कथित दान चोरी प्रकरण को लेकर विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुंह वक्फ की जमीन में हुए हजारों करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं खुलता। ये लोग एक घटना को पकड़ कर हिन्दू आस्था को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। जबकि उस पूरे प्रकरण के एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां 384 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को युवाओं को रोजगार मिलना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि यह नौजवान जब कार्य करेंगे तो जातिवादी राजनीति समाप्त होगी। विपक्ष फिर से जाति के आधार पर समाज के ताने–बाने को बांटना चाहता है। छिन्न–भिन्न करना चाहता। हमें इससे ऊपर उठना होगा। उन्होंने कहा कि यह लोग किस–किस प्रकार के मुद्दे को लेकर आते हैं। कोई मुद्दा नया नहीं होता है। जाति के नाम पर विभाजन या फिर आस्था पर प्रहार इनका मुद्दा होता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से उनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी साजिश हो रही है। किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए जब कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं। कांग्रेस कहती थी कि कृष्णा हुए ही नहीं। अयोध्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाल आंसू बहा रही थीं। आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, आप लोग सब देख रहे होंगे।

युवाओं और महिलाओं में राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प दिख रहा – नितिन नबीन

जम्मू , (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को जम्मू पहुंचे। हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर जम्मू–कश्मीर आने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठकें की गईं और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू–कश्मीर भाजपा की गतिविधियों की समीक्षा की गई। नितिन नबीन ने कहा कि संगठन को लगातार सक्रिय बनाए रखने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर की जनता से भाजपा को जो समर्थन और आशीर्वाद मिला है, उसके आधार पर पार्टी कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका में भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को पूरी सजगता से उठाते रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद जम्मू–कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिली, जिससे यहां के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू–कश्मीर की जो छवि दुनिया के सामने पेश की जाती थी, वह अब बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद जम्मू–कश्मीर विकास के साथ भारत का अभिन्न हिस्सा बनकर उभरा है।

गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 70 लाख पौधरोपण अभियान का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) राजधानी के 34 स्थानों पर 'मेगा वृक्षारोपण अभियान' चलाएगी। अभियान का उद्देश्य राजधानी में हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि विशेष अभियान के तहत परिषद ने 600 पौधे और 50,000 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए

50,000 से अधिक रोपण गड्ढे पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। अभियान के दौरान पीपल, नीम, जामुन, इमली, चंपा, अशोक, गुलमोहर और अमलतास जैसे देशी एवं पर्यावरण–अनुकूल वृक्ष लगाए जाएंगे। चहल ने बताया कि एनडीएमसी अपने हरित क्षेत्रों की जैव विविधता और सौंदर्य बढ़ाने के लिए हैमेलिया, जस्टिसिया, कैना, लिली, मुर्रेया सहित कई सजावटी और देशी प्रजातियों की झाड़ियां भी लगाएगी। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी सदस्य, विभागाध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कर इस अभियान में भाग लेंगे। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने कहा कि परिषद के लिए पौधरोपण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सतत जन आंदोलन है। उन्होंने बताया कि 'एक पेड़ मां के नाम रविवार को' अभियान के तहत लगातार 31 रविवार तक सफलतापूर्वक पौधरोपण अभियान चलाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों, विशेष अवसरों और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नियमित रूप से पौधरोपण किया जाता है।

भारत-बहरीन संबंध होंगे और मजबूत, जयशंकर ने की अहम मुलाकात

मनामा, (एजेंसी)। भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने सोमवार को बहरीन के मनामा में अपने समकक्ष अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्र में चल रहे हालात पर चर्चा की। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने बहरीन नेतृत्व का भारतीय समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी से मिलकर खुशी हुई। भारतीय समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की और क्षेत्र में चल रहे हालात पर विचारों का आदान–प्रदान किया।" जयशंकर अपनी कतर की यात्रा पूरी करने के बाद बहरीन पहुंचे थे। दोहा दौरे के दौरान उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री

शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की और कतर में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। यह उनके छह देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव है। बहरीन में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद वे कुवैत, ओमान, अमेरिका और ब्रूसेल्स की यात्रा करेंगे। दो मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने बहरीन पर हुए हमलों की निंदा की और देश के लोगों के साथ एकजुटता जताई। पीएम मोदी ने बहरीन में रह रहे भारतीय समुदाय को दिए जा रहे लगातार समर्थन के लिए राजा का धन्यवाद भी किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था, "बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से एक उपयोगी टेलीफोन बातचीत हुई। भारत बहरीन पर हुए हमलों की निंदा करता है और इस कठिन समय में उसके लोगों के साथ खड़ा है। मैं वहां रह रहे भारतीय समुदाय को दिए जा रहे मजबूत समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं।" यह बातचीत पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान हुई थी, जो फरवरी में तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान की मिसाइल क्षमता और सैन्य ढांचे को कमजोर करने के लिए संयुक्त हमले किए थे।

ईसीएलजीएस 5.0 के तहत 4.11 लाख से ज्यादा की गारंटी, 1.55 लाख करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) 5.0 के तहत लॉन्च होने के बाद से अब तक 4,11,497 गारंटी जारी की जा चुकी हैं, और इसके तहत कुल 1,55,229 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है, जो यह दर्शाता है कि बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली ने इस योजना को तेजी से अपनाया है। सरकार के अनुसार, 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई यह योजना पश्चिम एशिया में भू–राजनीतिक तनाव से प्रभावित कारोबारों को तेजी से और बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम को कम करने का काम करती है, ताकि वे पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करा सकें। इससे कंपनियों को नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) से जुड़ी समस्याओं से उबरने और अपने कारोबार को सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिलती है। वित्त

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि योजना के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर 100 प्रतिशत गारंटी और अन्य कारोबारी वर्गों के लिए 90 प्रतिशत गारंटी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वित्तीय संस्थानों का भरोसा बढ़ा है और जरूरतमंद क्षेत्रों तक तेजी से ऋण पहुंचाना संभव हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 के शुरुआती नतीजे यह साबित करते हैं कि सरकार एक मजबूत, त्वरित और भरोसेमंद ऋण व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि जैसे–जैसे इस योजना का दायरा बढ़ेगा ।

सम्राट चौधरी का ऐलान, प्राइवेट वाहनों पर टोल टैक्स नहीं

अररिया, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में टोल टैक्स को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार निजी (प्राइवेट) वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि केवल व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा, जबकि परिवार के साथ यात्रा करने वाले निजी वाहन चालकों को सरकार राहत देगी। अररिया जिले के फारबिसगंज में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग टोल टैक्स को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है और सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा, ष्टोल टैक्स तो कमर्शियल गाड़ियों पर लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं, उन्हें हमारी सरकार जरूर राहत देगी। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से तय किया है कि जो प्राइवेट गाड़ियां होंगी, उन पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। केवल कमर्शियल गाड़ियों से ही टैक्स लिया जाएगा।ष उन्होंने कहा कि टोल टैक्स संबंधी व्यवस्था भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी और राज्य सरकार ने आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी वाहनों को राहत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सहयोग शिविरों की उपयोगिता का भी उल्लेख किया।

प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़,चंदा चोरी घटना का राम नगरी मे नहीं दे रहा असर

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार श्रीवास्तव

अयोध्या।राम मंदिर से चंदा चोरी की घटना के बाद भी प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करने वाले आने वाले दूर–दराज व देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।जैसे पहले भीड़ रहती थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस समय भी रामनगरी में दिखाई दे रही है।राम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि चंदा चोरी की घटना अलग की बात है।उसकी जांच हो रही है।लोगो का मानना है कि भगवान श्रीराम के प्रति उनकी आस्था अटूट है और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।इस समय देश के विभिन्न राज्यों व जिलों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच रहे हैं।मंदिर परिसर में दर्शन–पूजन का क्रम सामान्य रूप से जारी है।श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, और अयोध्या हमारी सनातन आस्था की प्रतीक है।हम राम लला के दर्शन को आए हैं जिनसे हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है।मथुरा से दर्शन करने आई श्रद्धालु शालनी पाण्डेय व उनके परिजनों ने कहा कि वह रामलला के दर्शन के लिए आई हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस एवं एसआईटी अपना कार्य पूरी निष्पक्षता से कर रही है।इस घटना का उनकी आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।जयपुर से आए श्रद्धालु भानुप्रताप सिंह व उनके साथ आए अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जांच अपनी जगह है और दर्शन अपनी जगह। उन्हें न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह बनी हुई है।होटल, धर्मशालाएं, बाजार और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं तथा पूरे शहर में धार्मिक

वातावरण बना हुआ है।स्थानीय लोगो ने कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान श्रीराम और यहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का जिस तरह विकास हुआ है,उससे देश–विदेश के श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हुआ है।दुकानदारों ने बताया कि उनकी दुकान पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।सुबह से देर रात तक बाजारों में खरीदारी, प्रसाद और अन्य धार्मिक सामग्री की बिक्री सामान्य रूप से हो रही है।लोगों को जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है।व्यवसायी श्याम गुप्ता ने कहा कि उनकी दुकान पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा सामग्री, गमछा और धार्मिक वस्तुएं खरीदने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सड़क, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में हुए सुधार का लाभ व्यापारियों और श्रद्धालुओं दोनों को मिला है।सरयू घाट पर फोटोग्राफी का कार्य करने वाले मनीष मोदनवाल ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू स्नान और राम लला के दर्शन के बाद अपनी यादगार तस्वीरें खिंचवाने पहुंच रहे हैं। घाटों पर पहले जैसी ही रौनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था भगवान श्रीराम और मां सरयू के प्रति है, इसलिए किसी घटना से उनके विश्वास पर कोई असर नहीं पड़ा है। ई–रिक्शा चालक राजू पाल ने कहा कि वह प्रतिदिन श्रद्धालुओं को राम मंदिर, सरयू घाट और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंचाते हैं।पिछले दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।बेहतर सड़कें, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए विकसित सुविधाओं से पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिला है।देखा जाए तो हनुमानगढ़ी पर भी श्रद्धालुओं के भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है।

संपादकीय

बड़ी कीमत भावी पीढ़ियों को चुकानी होगी

सरकारों का ऋण लेना अपने–आप में समस्या नहीं है, बशर्ते निवेश उत्पादक योजनाओं या दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में हो। मगर, फिलहाल ज्यादातर रकम का इस्तेमाल नकदी ट्रांसफर के लिए हो रहा है। वोट खरीद योजनाएं का असर जाहिर होने लगा है। पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकारों ने बाजार से 15.2 फीसदी ज्यादा कर्ज उठाया। ज्यादा कर्ज लेने की होड़ का असर ब्याज दरों पर दिखा। मतलब यह कि अब सरकारों को अधिक महंगी दर पर ऋण लेना पड़ रहा है। भारत सरकार को दस साल के बॉन्ड बेचने के लिए अब लगभग सात प्रतिशत की दर से ब्याज देने पड़ रहे हैं। सरकारों का ऋण लेना अपने–आप में समस्या नहीं है, बशर्ते जुटाई गई रकम का निवेश उत्पादक योजनाओं या दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में हो रहा हो। मगर, अपने देश में फिलहाल इनमें से बड़ी रकम का इस्तेमाल मतदाताओं के खाते में नकदी ट्रांसफर के लिए हो रहा है। मार्केट रिसर्च एजेंसी क्राइसिल के मुताबिक 2019 तक सिर्फ चार राज्यों में कैश ट्रांसफर की योजनाएं थीं, जबकि अब 28 राज्यों और केंद्र शासित दिल्ली में इन्हें चलाने का बोझ सरकारों पर है। प्रोजेक्टडीप नामक एक संगठन की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के बाद से ऐसी योजनाओं पर सरकारी खर्च में 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये व्यय अब दो लाख 85 हजार करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच चुकी है। यह भी गौरतलब है कि ये सारी रकम सिर्फ कर्ज लेकर नहीं जुटाई गई है। बल्कि एक्सिस रिसर्च ने पिछले साल अपनी एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा था कि इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारों की व्यय प्राथमिकता में परिवर्तन लाकर और राजकोषीय घाटा बढ़ाते हुए पूरा किया गया है। व्यय प्राथमिकता में परिवर्तन का मतलब है कि दीर्घकालिक एवं मानव विकास की योजनाओं का बजट काट कर प्रत्यक्ष नकदी ट्रांसफर की योजनाएं बढ़ाई गई हैं। चूंकि सरकारें ऐसी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन नहीं करवातीं, इसलिए यह सामने नहीं आ पाता है कि मतदाताओं को तुरंत मिलने राहत की कितनी बड़ी कीमत भावी पीढ़ियों को चुकानी होगी। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रह्मण्यम ने इन योजनाओं को श्नई कल्याणकारी दृष्टि्य कहा है। इससे मतदाताओं को महसूस होता है कि उनके लिए कुछ किया गया है। लेकिन यह किस कीमत पर हुआ है, यह बताने वाला उनके आसपास कोई मौजूद नहीं होता!

परिवर्तन की जड़ेंरुई-गवर्नेंस से बदलता ग्रामीण भारत

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

कुछ क्षण केवल एक उपलब्धि भर नहीं होते, वे एक पूरी यात्रा को रोशन कर देते हैं। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चार पंचायती राज पहलों का चयन ऐसा ही एक क्षण है, ऐसा क्षण जो किसी एक कार्यालय का नहीं, बल्कि हर ग्राम पंचायत और हर उस नागरिक का है, जिसने डिजिटल रूप से सशक्त ग्रामीण भारत के सपने पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर, भारत की पंचायतें भरोसे, तकनीक और परिवर्तन का एक नया अध्याय लिख रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के बारह परिवर्तनकारी वर्षों के इस पड़ाव पर यह सम्मान विशेष महत्व रखता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं मात्र योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित निकायों से आगे बढ़कर, शासन की तीसरी स्तरीय व्यवस्था की आत्मविश्वासी, सक्षम और तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं के रूप में स्थापित हुई हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्कृष्ट लोक सेवा वितरण के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस वर्ष सात श्रेणियों में चयनित 17 परियोजनाओं में से 4 पंचायती राज क्षेत्र से संबंधित हैं, जो जमीनी स्तर पर नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु पिछले बारह वर्षों के निरंतर प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम है। ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख पहल, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, को डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के आने से पहले, देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कोई मानकीकृत, डेटा आधारित राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध नहीं था। आज यह सूचकांक डेटा, प्रदर्शन, पहचान और जनभागीदारी को आपस में जोड़ने वाली एक पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। उल्लेखनीय यह है कि दो ग्राम पंचायतों ने अपने स्वयं के प्रयासों से यह सम्मान अर्जित किया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले की कडेपुर ग्राम पंचायत ने ग्रासरूट स्तर की पहलों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से 1,300 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, पश्चिम त्रिपुरा की बिजय नगर ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार मिला है। पंचायत ने अपने स्वयं के स्रोतों से आय में लगभग 194 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और महिलाओं के बीच शत–प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल की है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग को श्ई–आरोग्य धमनीय पहल के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया। ये पुरस्कार मिलकर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। ई–गवर्नेंस में उत्कृष्टता अब केवल राज्यों की राजधानियों या जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समान रूप से हमारे गांवों और ग्राम सभाओं में भी स्थापित हो चुकी है। इस वर्ष 30 राज्यों की 1.65 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इसमें भाग लिया, जो हमारे द्वारा मिलकर तैयार की गई संस्थागत क्षमता और विश्वास को दर्शाता है। यह उपलब्धि संयोग से नहीं मिली है। पिछले बारह वर्षों में मंत्रालय ने पंचायतों को निरंतर बेहतर साधन उपलब्ध कराए हैं। ई–ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2.59 लाख से अधिक पंचायतों में योजना निर्माण, बजट और भुगतान प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ?3.16 लाख करोड़ से अधिक के ऑनलाइन लेन–देन संभव हुए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सभासार प्लेटफॉर्म, जो 23 भारतीय भाषाओं में कार्य करता है, अब 1.35 लाख से अधिक पंचायतों में चंद मिनटों में ग्राम सभा की कार्यवाही तैयार कर देता है। मेरी पंचायत ऐप, जिसे 1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, विकास कार्यों की जानकारी सीधे नागरिकों तक पहुंचा रहा है। इन प्रयासों के साथ–साथ, स्वामित्व योजना के तहत 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है तथा जून 2026 के मध्य तक 1.94 लाख गांवों के लिए 3.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों के संपत्ति अधिकार सुदृढ़ हुए हैं और उन्हें ऋण सुविधा प्राप्त करने में आसानी हुई है। पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि में ग्रामीण स्थानीय निकायों को ?2.82 लाख करोड़ की अनुदान राशि जारी की गई, जो अब तक की सर्वाधिक है।

नितिन गडकरी की ई20 नीति की वजह से खराब हो रही हैं गाड़ियां

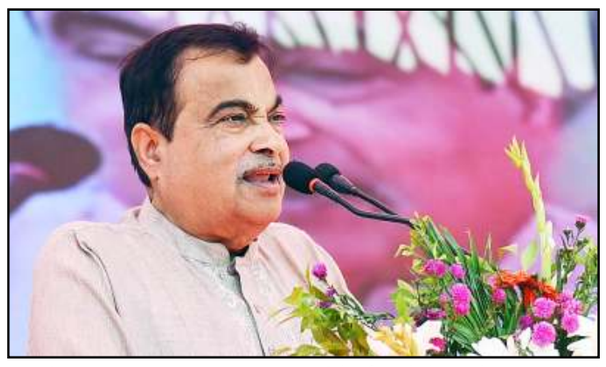

नीरज

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर इन दिनों चौतरफा हमले हो रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ई20 पेट्रोल को वाहनों की खराबी का कारण बताया जा रहा है, तो कभी सड़कों पर उतरने की चेतावनी देकर केंद्र सरकार की एथनॉल नीति के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो लंबे समय से एथनॉल मिश्रित ईंधन को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बताते रहे हैं, अब उसी नीति को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में हैं। हम आपको बता दें कि ई20 यानी पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिश्रण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ताजा मामले में बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपनी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में आई खराबी का आरोप सीधे ई20 पेट्रोल और सरकार की नीति पर लगाया है। मनीष का दावा है कि उनकी दो महीने पुरानी और लगभग 12 हजार किलोमीटर चली गाड़ी का इंजन अचानक खराब हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्यूल टैंक से निकाले गए पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल और अशुद्धियां मिलीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह काफी भावुक नजर आए और बोले कि लाखों रुपये खर्च कर खरीदी गई गाड़ी इतनी जल्दी खराब हो जाना गंभीर चिंता का विषय है। देखा जाये तो मनीष कश्यप अकेले नहीं हैं। देशभर में हजारों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन परफॉर्मेंस कम होने और वाहनों में तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। कई वीडियो में गुलाबी रंग का पेट्रोल, टंकी में पानी जैसी परत और अन्य अशुद्धियां दिखाकर दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक है। हालांकि सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय इन दावों को खारिज कर रहे हैं। सार्वजनिकनीति इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रूप भी ले लिया है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ई20 नीति के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। ष्टीम भारत अगेंस्ट द एथनॉल स्कैमष के बैनर तले प्रस्तावित इस प्रदर्शन को एथनॉल नीति के खिलाफ पहला बड़ा सार्वजनिक आंदोलन बताया जा रहा है। पूनावाला का कहना है कि लोग एथनॉल नीति के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसकी जल्दबाजी में की गई क्रियान्वयन प्रक्रिया और उपभोक्ताओं को विकल्प न दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो कुछ लोग नितिन गडकरी के आवास के बाहर धरने पर बैठ सकते हैं। देखा जाये तो विवाद केवल वाहन खराबी तक सीमित नहीं है। एक उद्योगपति ने भी सरकार की ई20 नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि सरकार जनता के सामने इस योजना को पूरी तरह सफल बता रही है, लेकिन अदालत में इसे अभी भी ष्चल रहा प्रयोगष बताया गया। हालांकि बाद में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस दावे को गलत बताया। वहीं उक्त उद्योगपति का कहना है कि असली चिंता उन उद्योगों और निवेशकों की है जिन्होंने सरकार की नीति पर भरोसा करके एथनॉल संयंत्रों में अरबों रुपये का निवेश किया। यदि एथनॉल की खरीद और मांग ही निश्चित नहीं है, तो निवेशकों को किस भरोसे निवेश के लिए प्रेरित किया गया। हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा था, जिसमें एथनॉल आवंटन प्रक्रिया को दोबारा खोलने की बात कही गई थी। इस सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठा कि सरकार द्वारा एथनॉल खरीद की बाध्यता वास्तव में कितनी मजबूत है। आलोचकों का कहना है कि यदि खरीद केवल ष्सर्वश्रेष्ठ प्रयासष के आधार पर होगी तो उद्योगों की वित्तीय स्थिरता पर खतरा पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एथनॉल नीति के आर्थिक और कृषि प्रभावों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ई20 कार्यक्रम भारत को विदेशी मक्के और उससे बने उत्पादों पर अधिक निर्भर बना सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि यह नीति अब किसान केंद्रित कम और आयात आधारित ढांचे जैसी अधिक दिखाई देने लगी है। उन्होंने सरकार से ई20 की अनिवार्यता पर पुनर्विचार कर ई5 या ई10 जैसे विकल्प फिर से उपलब्ध कराने की मांग की है। ऑटोऔर वाहन वहीं देशी और विदेशी वाहन निर्माता कंपनियों ने ई20 पेट्रोल को लेकर मिश्रित लेकिन संतुलित रुख अपनाया है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा और किआ जैसी कंपनियों ने कहा है कि अप्रैल 2023 के बाद बने अधिकांश नए वाहन ई20 अनुकूल बनाए जा चुके हैं और उनमें इस ईंध न के इस्तेमाल से कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नहीं है। वाहन उद्योग संगठन सियाम ने भी माना है कि ई20 से माइलेज में लगभग 2 से 4 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे स्थायी इंजन क्षति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहीं महिंद्रा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि ई20 सुरक्षित तो है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ सकता है। टोयोटा सहित कई कंपनियों ने अपने नए पेट्रोल मॉडलों को ई20 अनुकूल घोषित किया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों और कंपनियों ने पुराने वाहनों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार इस योजना का बचाव कर रही है। सरकार का दावा है कि भारत ने निर्धारित समय से पहले दिसंबर 2025 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम से देश को 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत हुई, किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारी कमी आई। सरकार का कहना है कि इससे 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का विकल्प तैयार हुआ। सरकार का यह भी कहना है कि वाहन कंपनियों और सियाम के साथ व्यापक चर्चा के बाद ही ई20 लागू किया गया और कई निर्माता वर्ष 2009 से ही ई20 अनुकूल इंजन विकसित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी माइलेज घटने के दावों को मामूली बताया है। उनका कहना है कि एथनॉल मिश्रित ईंधन से इंजन की नॉकिंग कम होती है और वाहन की गति क्षमता बेहतर होती है। वहीं नितिन गडकरी ने एथनॉल विरोधी प्रचार को ष्पेड कैंपेनष करार दिया है। उनका आरोप है कि पेट्रोलियम लॉबी भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से परेशान है और इसलिए दुष्प्रचार कर रही है। गडकरी ने यह चुनौती भी दी कि दुनिया में कोई एक उदाहरण दिखाया जाए जहां ई20 पेट्रोल से वाहन स्थायी रूप से खराब हुए हों। तेलऔर गैस बहरहाल, फिलहाल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एक ओर सरकार इसे किसानों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो दूसरी ओर उपभोक्ता, वाहन मालिक और कुछ उद्योग विशेषज्ञ इसके प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। आने वाले समय में यह बहस केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों, अदालतों और राजनीतिक मंचों तक और तेज होती दिखाई दे सकती है।

नजर आ रहे खतरे से बचाव नहीं, भूकंप से कैसे बचाएंगी सरकारें

योगेंद्र

वेनेजुएला में एक मिनट के अंदर दो बड़े विनाशकारी भूकंप में करीब दो हजार लोगों की मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 10 हजार लोग घायल हो गए। बगैर किसी चेतावनी के आने वाली भूकंप जैसी आपदाएं सरकारों को चेताती हैं कि पहले से बचाव के उपाए किए जाएं, ताकि कम से कम जानमाल का नुकसान हो सकें। भूकंप का खतरा भारत मे भी है। देश के कई हिस्सों में कई बार शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। सवाल यह है कि पूर्व में आए इन भूकंपों से देश की सरकारों ने कोई सबक सीखा है। क्या देश में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि भूकंप आने पर कम से कम जानमाल का नुकसान हो। दरअसल भारत के राजनीतिक दलों और सरकारों से किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले और बाद में बचाव की ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। कारण साफ है केंद्र और राज्यों की सरकारों को सामने स्पष्ट नजर आते हुए खतरों से लोगों को बचाने का कोई इंतजाम नहीं हो, वे भूकंप जैसे छिपे हुए खतरों से कैसे बचाएंगे। दिल्ली के बाद लखनउ में आग से 15 लोगों की मौत हो गई। ऐसी लाखों इमारतें अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें आग से बचाने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। जब दिल्ली में आग लगी तभी राज्यों की सरकारों को सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकारों ने लोगों की जान की परवाह नहीं की। अगले ही दिन बिहार के मुजफ्फरपुर में आग ने पांच–छह मरीजों को लील लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा और फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में आग ने फ्लैट और शोरूम खाक कर दिए। तीन दिन में आग की चार भयानक घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है और करीब 26 लोगों की जलकर या काले धुएं की चपेट में आकर मौत हो गई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनुमानों के अनुसार, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों के 60 प्रतिशत से अधिक छोटे और मध्यम भवन बिना वैध फायर एनओसी के चल रहे हैं। देश भर में दमकल केंद्रों में 97.5 प्रतिशत, दमकल कर्मियों में 96.2 प्रतिशत और अग्निशमन उपकरणों में लगभग 80 प्रतिशत तक की कमी है। देश के लगभग हर बड़े शहर में सुरक्षा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। यह खतरा ऐसा है, जो साफ दिखाई देता है। इससे बचाव के शतकृप्रतिशत इंतजाम भी किए जा सकते हैं। इसके बावजूद राज्यों और केंद्र ने पूर्व में हुए ऐसे हादसों से सबक नहीं सीखा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है, सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे खतरे से निपटने में सरकारें नाकाम हैं तो भूंकप जैसी अचानक आने वाली आपदा और उसके भयावह रूप से सरकारें कैसे निपटेंगी। जबकि भूगर्भ वैज्ञानिक साफ चेता चुके हैं कि देश के कितने हिस्सों में कभी भी भीषण भूकंप आ सकता है। पिछले दो दशकों में देश में 10 बड़े भूकंप आए हैं, जिनमें 20,000 से अधिक लोगों की जान गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ इमारतें भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आती हैं। इनमें से कई इमारतें 30–40 साल पहले बनी थीं और इनमें से कई इमारतें नेशनल बिल्डिंग कोड्स का पालन नहीं करती हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में जोन–1 में भूकंप आने की आशंका सबसे कम रहती है, वहीं जोन–5 में ज्यादा प्रबल रहती है। दिल्ली–एनसीआर का इलाका सीस्मिक जोन–4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सीस्मिक गतिविधियाँ तेज रहती हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत के कघ्रीब 59: भू–भाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। जानकार सीस्मिक जोन–4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं। गौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सीस्मिक जोन–3 की श्रेणी में आते हैं। जबकि भूगर्भशास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा यह भी है कि वह हिमालय के निकट है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टॉनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खघमियाजा भुगतना पड़ सकता है। नेशनल सेंटर फोर सिसमोलॉजी के मुताबिक भारत के 29 शहरों पर भूकंप का गंभीर खष्तरा है। इन शहरों में दिल्ली समेत नौ राज्यों की राजधानियां भी हैं। ये ज्यादातर शहर हिमालय जोन से लगे हैं। हिमालय से लगे शहर दुनियां के उन शहरों में शुमार हैं, जहां भूकंप का सबसे ज्यादा खष्तरा रहता है। दिल्ली, पटना, श्रीनगर, कोहिमा, पुडुच्चेरी, गुवाहाटी, गंगटोक, शिमला, देहरादून, इम्फाल और चंडीगढ़ भूकंपीय क्षेत्र के जोन चार और पांच में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी) के मुताबिक ये वो शहर हैं जहां आबादी का घनत्व बहुत सघन है और ये गंगा के मैदानी भाग हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि सिस्मिक जोन–4 में आने वाली राजधानी दिल्ली भूकंप के बड़े झटके से खासा प्रभावित हो सकती है। अगर यहां 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो दिल्ली की कई सारी इमारतें और घर रेत की तरह भरभराकर गिर जाएंगे। ऐसा इसलिए है, क्योंकि दिल्ली की इमारतों में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री ऐसी है, जो भूकंप के झटकों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। दिल्ली में मकान बनाने की निर्माण सामग्री ही आफत की सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली में 1760 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इन अनधिकृत कॉलोनियों में गैर–इंजीनियरिंग इमारतें बनी हैं, जिनमें भूकंप प्रतिरोध क्षमता शायद ही हो। भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील और खतरनाक माने जाने वाले जोन पांच में भारत का पूरा पूर्वोत्तर है। इनमें जम्मू–कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के साथ उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार हैं। वहीं जम्मू–कश्मीर का कुछ हिस्सा, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र का कुछ भाग जोन चार में हैं। गुजरात का भुज 2001 में भयावह तरीकेे से भूकंप की चपेट में आया था।

नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल

आर. सूर्यामूर्ति

गाजा संघर्ष ने प्रमुख शक्तियों के दोहरे मानदंडों की बहस को भी तेज किया है। अमेरिका इजरायल की सुरक्षा का समर्थन करते हुए मानवीय स्थिति पर चिंता जताता है। यूरोपीय देशों के भीतर भी मतभेद दिखाई देते हैं, जबकि रूस और चीन अंतरराष्ट्रीय कानून की बात करते हैं, लेकिन स्वयं भी ऐसे आरोपों से घिरे रहे हैं। सयुक्त राष्ट्र की हालिया स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट ने इजरायल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जारी हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों की गंभीर तस्वीर पेश की है। यह रिपोर्ट केवल अत्याचारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता खोती जा रही है।द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित थी कि कोई भी देश, सेना या सशस्त्र संगठन अंतरराष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं होगा। इसी उद्देश्य से जिनेवा कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, ताकि शक्ति पर कानून का नियंत्रण बना रहे। लेकिन गाजा और कब्जे वाले पश्चिमी तट की स्थिति यह संकेत देती है कि ये संस्थाएं अब जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय केवल उल्लंघनों का रिकॉर्ड तैयार करने तक सीमित होती जा रही हैं।रिपोर्ट के अनुसार, कब्जा और अधिक गहरा हुआ है, बस्तियों का विस्तार तेज हुआ है और आम नागरिकों की पीड़ा सामान्य स्थिति बन गई है। रिपोर्ट इजरायल पर ऐसे हालात बनाने का आरोप लगाती है, जिनमें बसने वालों की हिंसा राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनती जा रही है। दूसरी ओर, रिपोर्ट हमास द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ फांसी, यातना और भय का वातावरण बनाकर नियंत्रण स्थापित करने की भी चर्चा करती है। इस संघर्ष में आम नागरिक एक ओर राज्य की सैन्य शक्ति और दूसरी ओर उग्रवादी हिंसा के बीच फंस गए हैंइजरायल अपनी सुरक्षा और सात अक्टूबर के हमलों का हवाला देता है, जबकि फिलिस्तीनी दशकों से चले आ रहे कब्जे, विस्थापन और सैन्य कार्रवाई की ओर ध्यान दिलाते हैं। दोनों पक्षों के अपने–अपने तर्क हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नागरिकों पर हमले, बंधक बनाने, सामूहिक दंड, यातना या जबरन जनसंख्या परिवर्तन को उचित नहीं ठहरा सकता। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के दौरान भी मानवीय सीमाएं तय करने के लिए बनाया गया है।रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि अत्याचारों के दस्तावेजीकरण और जवाबदेही के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। आज संयुक्त राष्ट्र उपग्रह चित्रों, डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकों और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के माध्यम से पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने में सक्षम है। इसके बावजूद राजनीतिक स्तर पर कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। रिपोर्टें तैयार होती हैं, आपात बैठकें बुलाई जाती हैं, और प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हिंसा और मानवीय संकट जारी रहते हैं। पश्चिमी तट की स्थिति इस विफलता को और स्पष्ट करती है। लंबे समय तक बसने वालों की हिंसा को कुछ चरमपंथी व्यक्तियों की अलग–थलग घटनाओं के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन आयोग का कहना है कि हमलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और फिलिस्तीनी समुदायों की सुरक्षा में लगातार विफलता ने दंडमुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। जब हिंसा का इस्तेमाल समुदायों को विस्थापित करने, जनसांख्यिकीय बदलाव लाने और क्षेत्रीय नियंत्रण बदलने के लिए होने लगे, तो वह केवल कानून–व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह जाती, बल्कि नीति का साधन बन जाती है। रिपोर्ट हमास की भूमिका पर भी उतनी ही स्पष्ट है। इसमें बताया गया है कि संगठन ने फांसी, यातना और सार्वजनिक भय के जरिए अपने नियंत्रण को मजबूत किया। यह निष्कर्ष उन चयनात्मक राजनीतिक धारणाओं को चुनौती देता है, जिनमें एक पक्ष को पूरी तरह सही और दूसरे को पूरी तरह गलत मान लिया जाता है। यदि मानवाधिकारों का मूल्यांकन राजनीतिक निष्ठा के आधार पर होने लगे, तो कानून की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाएगी। रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि यह संकट केवल गाजा तक सीमित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार कई बार ऐसे समय सामूहिक कार्रवाई को रोक देता है, जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। गाजा, यूक्रेन, सूडान और म्यांमार जैसे संघर्षों में बार–बार यही स्थिति देखने को मिली है कि प्रस्ताव आते हैं, कूटनीतिक गतिरोध बना रहता है और आम नागरिक सबसे अधिक कीमत चुकाते हैं। गाजा संघर्ष ने प्रमुख शक्तियों के दोहरे मानदंडों की बहस को भी तेज किया है। अमेरिका इजरायल की सुरक्षा का समर्थन करते हुए मानवीय स्थिति पर चिंता जताता है। यूरोपीय देशों के भीतर भी मतभेद दिखाई देते हैं, जबकि रूस और चीन अंतरराष्ट्रीय कानून की बात करते हैं, लेकिन स्वयं भी ऐसे आरोपों से घिरे रहे हैं। इससे विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देशों में यह धारणा मजबूत हुई है कि नियम–आधारित व्यवस्था सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होती। यदि जवाबदेही चयनात्मक दिखाई देगी, तो देश कानूनी दायित्वों के बजाय राजनीतिक संरक्षण की गणना करने लगेंगे। इसका प्रभाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर की सेनाएं और सशस्त्र संगठन गाजा को भविष्य के युद्धों के लिए एक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। यदि मानवीय कानून के उल्लंघन की राजनीतिक कीमत लगातार घटती गई, तो भविष्य के संघर्ष और अधिक क्रूर हो सकते हैं। इस संघर्ष का सबसे गहरा प्रभाव अगली पीढ़ी पर पड़ेगा। फिलिस्तीनी बच्चे विस्थापन, अभाव और हिंसा के बीच बड़े हो रहे हैं, जबकि इजरायली बच्चे आतंकवाद, असुरक्षा और कठोर होती राजनीतिक सोच के माहौल में जीवन जी रहे हैं। भवन और सड़कें दोबारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन विश्वास और सामाजिक संबंधों का पुनर्निर्माण कहीं अधिक कठिन होता है। केवल युद्धविराम, मानवीय सहायता या पुनर्निर्माण स्थायी समाधान नहीं दे सकते। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जवाबदेही की उस व्यवस्था को मजबूत करना होगा, जिसमें जांच केवल अभिलेख तैयार करने तक सीमित न रहे, बल्कि उसके आधार पर कानूनी, कूटनीतिक और राजनीतिक कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। गाजा का सबसे बड़ा नुकसान केवल वहां की तबाह इमारतें और बिखरे जीवन नहीं, बल्कि यह भी हो सकता है कि दुनिया का यह विश्वास ही समाप्त हो जाए कि कानून अब भी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। एक बार यह विश्वास टूट गया, तो उसे दोबारा स्थापित करना किसी भी उजड़े शहर के पुनर्निर्माण से कहीं अधिक कठिन होगा।

संक्षिप्त खबरें

यूपी में पदोन्नत 158 खंड शिक्षा अधिकारियों को मिली तैनाती

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने पदोन्नति प्राप्त 158 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को नई तैनाती दे दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत अधिकांश अधिकारियों को विभिन्न जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी नई तैनाती स्थल पर योगदान देंगे। इस आदेश से लंबे समय से पदोन्नति के बाद तैनाती का इंतजार कर रहे अधिकारियों को राहत मिली है। अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से डायट में प्रशिक्षण, शैक्षणिक अनुसंधान और शैक्षिक गुणवत्ता सुधार से जुड़े कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

दिन में उमस ने किया बेहाल, शाम को झमाझम बारिश

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी में रविवार को दिनभर उमस ने लोगों को परेशान रखा। हालांकि, देर शाम मौसम ने करवट ली और करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान लखनऊ में 9.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक था। वहीं, न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ऊपर रहा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। इसके चलते 7 जुलाई से लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में रुक–रुककर अच्छी बारिश होने के आसार हैं।

बसपा का बढ़ रहा कुनबा, पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम की वापसी

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा अपना कुनबा भी बढ़ा रही है। पार्टी में पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम की वापसी हुई है। इन्हें लखनऊ का मुख्य मंडल प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा बुलंदशहर के मुकेश पंडित समेत कई दलों के नेता बसपा का हिस्सा बने हैं। नोएडा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सतवीर नागर को भी पार्टी में वापस लेकर मेरठ मंडल का जोनल प्रभारी बनाया गया है। आजाद समाज पार्टी के नेता आगरा के महेश चंद्रा ने भी रविवार को बसपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं, मऊ के मोहम्मदाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में जेके आजाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस मंडल में पूर्व के चुनावों में बसपा का खासा प्रभाव रहा है। इसी रणनीति के तहत बसपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन कर अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की कवायद में जुटी है। बसपा द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिये प्रत्याशियों की घोषणा करना अन्य दलों के लिए चुनौती बनता जा रहा है।

शिविर में ग्रामीणों की सुनीं समस्याएं

लखनऊ, संवाददाता। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के आपका विधायक, आपके द्वार अभियान के 174वें सप्ताह के तहत ताराखेड़ा ग्राम पंचायत में रविवार को शिविर लगा। इसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं, विकास कार्यों व जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। संबंधित विषयों के त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया गया। मेधावी विद्यार्थियों वंदना वर्मा (68 फीसदी), अनुराधा (67 फीसदी), सलमा (63 फीसदी) और ललित (60 फीसदी) को सम्मानित किया गया। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की सशक्त नींव है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान अन्य बच्चों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त, विजन प्लस के सहयोग से निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगा, जहां 50 जरूरतमंदों को निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी : महंत नृत्य गोपाल दास का बड़ा बयान, जताई नाराजगी

लखनऊ, संवाददाता। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं श्री मणिरामदास छावनी के महंत नृत्य गोपालदास ने राम मंदिर में कथित दान–चोरी की घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

महंत नृत्य गोपालदास द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि मंदिर में हुई कथित दान–चोरी से वे अत्यंत आहत हैं। इस तरह के कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वे इस मामले में दोषियों को बख्शेंगे नहीं। उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पत्र के अंत में महंत ने कहा है कि यह मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भगवान श्रीराम के नाम पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में बंद अन्य अलमारियों में मिल सकती हैं दवाएं

लखनऊ, संवाददाता। केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में करोड़ों रुपये के दवा घोटाले की जांच में अब नए खुलासे हो रहे है। विभाग में बंद अलमारियों को खोलने का सिलसिला जारी है। अलमारी में अब तक करीब 115 मरीजों के नाम पर जारी दवाएं मिल चुकी हैं। संस्थान इन दवाओं की कीमत तीन लाख से अधिक होने का दावा कर रहा है। वहीं, जांच समिति का कहना है कि अभी दो से तीन और अलमारियां बंद हैं, जिनमें अहम दस्तावेज और मरीजों की दवाएं मिल सकती हैं। समिति ने इन अलमारियों की चाबियां विभाग से मांगी हैं। सोमवार को इन्हें भी खोला जाएगा। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि बरामद दवाओं के उपयोग, उन्हें अलमारियों में रखने का कारण और संबंधित मरीजों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। हर दवा का मरीजों के रिकॉर्ड से मिलान कर सूची तैयार की जा रही है।

दूल्हा हत्याकांड धरने पर बैठी बहन सौम्या बिंद की तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल में भर्ती

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर, यूपी के जौनपुर में खेतासराय थाना क्षेत्र के चर्चित आजाद बिंद हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी मृतक की बहन सौम्या बिंद की सोमवार देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालत खराब होने पर उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सोमवार शाम धरना स्थल पर बैठे–बैठे सौम्या बिंद को चक्कर आने लगे, जिसके बाद मौजूद लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. सलमान अंसारी ने बताया कि डिहाइड्रेशन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी थी। फिलहाल उन्हें भर्ती कर इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है। विदित हो कि खेतासराय थाना क्षेत्र में 1 मई को बारात लेकर जा रहे आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजन और ग्रामीण 18 जून से कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व मृतक की बहन सौम्या बिंद कर रही हैं, जो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सौम्या बिंद का आरोप है कि प्रशासन ने आरोपियों के मकान ध्वस्त करने का आदेश दिए जाने का दावा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर केवल आश्वासन देकर मामले को टालने का आरोप लगाया। सौम्या बिंद ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं करता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। वहीं, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद धरना स्थल पर मौजूद लोगों में चिंता का माहौल रहा।

पुलिस मुठभेड़ पांच बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में गोलीय 8 तमंचे, देसी रिवॉल्वर और दो बाइक बरामद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जलालपुर और केराकत थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात हुई मुठभेड़ में पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। आरोपियों के कब्जे से आठ तमंचे, एक देसी रिवॉल्वर, कारतूस और दो मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं।इस संबंध में मंगलवार को जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी केराकत अजय कुमार राय ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के आयुष श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। केराकत पुलिस टेकूरीडीह के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच संदिग्ध पुलिस को देखकर पराऊगंज की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही जलालपुर पुलिस ने भी घेराबंदी कर दी। थोर बिंदे–टेकूरी मार्ग पर दोनों ओर से पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें सोनल वर्मा पुत्र संतोष वर्मा, निवासी बीरमपुर, थाना केराकत (घायल)राजेश्वर पाण्डेय पुत्र नेहरू पाण्डेय, निवासी एकौना, थाना गौराबादशाहपुर,अवनीश गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता, निवासी बीरमपुर, थाना केराकत बाबी कुमार पुत्र रामकुमार, निवासी मकसुदा मंडी, जालंधर (पंजाब)रंजीत कुमार पुत्र रवि कुमार, निवासी रतन नगर, जालंधर (पंजाब) पुलिस ने बताया कि सोनल वर्मा के खिलाफ पहले से लूट, जालसाजी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है।पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, हाईकोर्ट ने कहा– याचिका सुनवाई योग्य नहीं

लखनऊ, संवाददाता। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दानपात्रों से चढ़ावा चोरी के आरोपों वाले मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल जनहित याचिका (पी आई एल) को सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह कहते हुए शुरुआती सुनवाई पर याचिका निस्तारित कर दी कि यह मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में यह याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई को ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऑडिट कराने की मांग की गई थी मामले की सी बी आई से जांच कराने समेत चढ़ावे की संपत्ति का कैग से ऑडिट कराने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। इसमें, कथित गबन मामले की जांच समेत केस दर्ज करने के निर्देश सी बी आई को देने का कोर्ट से आग्रह किया गया है। साथ ही श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों में चढ़ावे के रूप में मिलने वाली नकद धनराशि, सोने चांदी के आभूषणों व अन्य कीमती वस्तुओं का आडिट महालेखा परीक्षक नियंत्रक (कैग) से कराने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा– भक्तों की भावनाओं को ठेस पंहुची याचिकाकर्ता का कहना है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम जी के मंदिर में दान व चढ़ावे की संपत्ति के कथित गबन के आरोपों का मामला अखबारों में छप रहा है। इससे भक्तों की भावनाओं को ठेस पंहुची है। ऐसे में इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच और ऑडिट होना आवश्यक है। याची ने राज्य सरकार को भी यह भी निर्देश देने की मांग की है कि मामले की तफ्तीश किसी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की देखरेख में कराई जाए। याचिका में केंद्र, राज्य सरकार के सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव, सी बी आई के निदेशक, कैग व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इसके चेयरपर्सन के माध्यम से पक्षकार बनाया गया था।

कला, साहित्य, समाज पर बुद्धिजीवियों से बीजेपी अध्यक्ष ने किया संवाद

लखनऊ, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को लखनऊ प्रवास के दौरान बुद्धिजीवियों, कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृतिकर्मियों से मुलाकात की। गोखले मार्ग स्थित विदुषी पद्मश्री डॉ. विद्या बिंदु सिंह के गोखले मार्ग स्थित आवास पर बैठक हुई, जहां उन्होंने लखनऊ सहित देश की सांस्कृतिक विरासत, साहित्य, कला और सामाजिक विकास पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान डॉ. विद्या विंदु सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दही–जलेबी खिलाई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंह और भाजपा

लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यकाल को रेखांकित किया। कहा कि सरकार ने जनकल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने प्रबुद्धजनों से अपील की कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने व देश की धरोहर को सहेजने में सक्रिय भूमिका निभाते रहें। बैठक के दौरान प्रबुद्धजनों और कलाकारों ने भी खुलकर विचार रखे। समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए सरकार और संगठन को सुझाव भी दिए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, लोकगायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित आत्म प्रकाश मिश्र, साहित्यकार भारती सिंह, पूर्व डीजीपी विजय कुमार, प्रो. पूर्णिमा पांडेय, डॉ. एएन सिंह शामिल रहे, जिन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बरावनकला स्थित पश्चिमी विधानसभा के बूथ संख्या चार के अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर जाकर उनका जन्मदिन मनाया। शिवाजी रावत को नितिन नवीन ने अंगवस्त्र पहनाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपाध्यक्ष नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष विमल चौधरी ने भी बधाई दी और शिवाजी रावत के संगठनात्मक कार्यों की सराहना की।

विराम खण्ड-5, गोमतीनगर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। महान राष्ट्रवादी, प्रख्यात शिक्षाविद एवं भारतीय संस्कृति के प्रेरणास्रोत स्वर्गीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती आज विराम खण्ड–5, गोमतीनगर, जनकल्याण समिति के तत्वावधान में अत्यंत श्रद्धा, उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों, माननीय सदस्यों एवं स्थानीय निवासियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनकल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ. भरत राज सिंह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे महान राष्ट्रवादी, दूरदर्शी शिक्षाविद तथा भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 1943 से 1946 तक वे हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्र भारत की प्रथम केंद्रीय सरकार में उन्होंने उद्योग एवं आपूर्ति तथा खाद्य एवं रसद मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। डॉ. सिंह ने आगे बताया कि लियाकत–नेहरू समझौते से असहमति व्यक्त करते हुए डॉ. मुखर्जी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए आजीवन संघर्ष किया। वर्ष 1953 में बिना परमिट जम्मू–कश्मीर प्रवेश करने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहाँ 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। उनका जीवन राष्ट्रहित, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियाँ निरंतर प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। इस अवसर पर जनकल्याण समिति, विराम खण्ड–5 के अध्यक्ष डॉ. भरत राज सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. एन. टंडन, संगठन सचिव प्रभात श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अतुल जौहरी, संचार सचिव मनोज शर्मा, संयुक्त सचिव प्रवीण मिश्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी तथा सदस्य संदीप मिश्रा सहित अनेक सम्मानित नागरिक एवं स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

राम मंदिर में कथित चंदा घोटाले के विरोध में कांग्रेस की सद्बुद्धि पदयात्रा, मंदिर में किया हनुमान चालीसा का पाठ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और चढ़ावे में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोपों को लेकर मंगलवार को जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस कार्यालय, सब्जी मंडी स्थित इंदिरा भवन से केरारवीर मंदिर तक श्सद्बुद्धि पदयात्राश निकाली। पदयात्रा का समापन सद्भावना पुल के पास स्थित केरारवीर मंदिर परिसर में हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी व चढ़ावा घोटाले के मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने की मांग की। पदयात्रा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में राम मंदिर में कथित लूट और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि चंदे और चढ़ावे में कथित घोटाला भगवान श्रीराम के भक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। वहीं, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर कथित मुख्य आरोपियों चंपतराय बंसल, नृपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ही अब राम के नाम पर हुए कथित घोटाले के आरोपों से घिरे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

यूपी में बनेगा नया रिकार्ड, एक दिन में लगेंगे 35 करोड़ पौधे

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाकर पौधरोपण का नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पौधारोपण महाभियान– 2026 को जनसहभागिता के साथ उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को जनप्रतिनिधियों से संवाद कर अधिकारियों को दिशा–निर्देश देंगे। वन मंत्री भी विभिन्न विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इस अभियान का नोडल विभाग होगा और सर्वाधिक 15.50 करोड़ पौधे लगाएगा। महाभियान में ग्राम्य

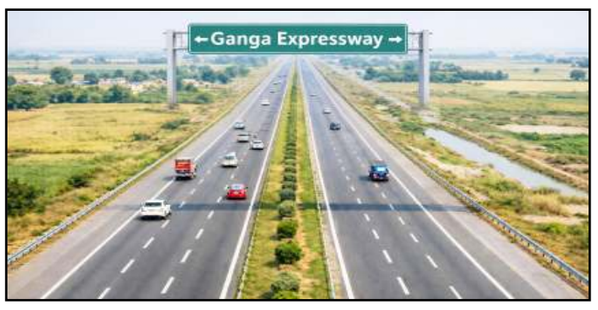

विकास विभाग 10 करोड़, कृषि 3.25 करोड़, उद्यान 1.50 करोड़ और पंचायती राज विभाग 1.22 करोड़ पौधरोपण करेगा। वन विभाग ने इस वर्ष अपनी करीब दो हजार नर्सरियों में 52.44 करोड़ पौधे तैयार किए हैं। इनका वितरण अभियान से पहले पूरा किया जाएगा। विशेष रूप से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 5.50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यहां पीपल, बरगद, नीम, पाकड़, गूलर, महुआ, आम, अर्जुन, अमलतास, कचनार और गुलमोहर जैसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सांस के रोगियों को मिल रही कब्ज दूर करने की दवा

लखनऊ, संवाददाता। केजीएमयू में श्वास रोगियों को सामान्य दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इनहेलर जैसी आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें ओपीडी में कब्ज दूर करने वाली दवाएं और एंटीबायोटिक दी जा रही है। दवाओं के इस संकट से गरीब मरीजों को बाहर भटकना पड़ रहा है। केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 250 से 300 मरीज आते हैं। उन्हें अपनी जेब से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। संस्थान को दवाओं के लिए करोड़ों रुपये का बजट मिलता है। इसके बावजूद श्वास संबंधी बीमारियों की सबसे सस्ती दवा डायरोफाइलीन भी नहीं मिल रही है। महंगे इनहेलर, वाइसिलॉन और मिथाइल स्टेरॉयड भी उपलब्ध नहीं हैं। विभाग की दवाओं की सूची में कई ऐसी दवाएं हैं जो श्वास रोगियों के लिए जरूरी नहीं है ओपीडी में दर्द निवारक ट्यूब, कब्ज दूर करने वाली दवाएं और एंटीबायोटिक बांटी जा रही है। विटामिन बी, पैरासिटामॉल, एल्बेंडाजोल, एंटासिड और विटामिन सी जैसी दवाएं भी वितरित हो रही हैं। मरीज, खासकर गरीब तबके के लोग, दवा के अभाव में भारी परेशानी झेल रहे हैं। उन्हें इनहेलर और अन्य सामान्य दवाएं बाहर से लेनी पड़ रही हैं। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि विभाग में सामान्य दवाओं की उपलब्धता कराए जाने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि मरीजों को परेशानी न हो।

सपा पूर्व मंत्री ने भ्रामक प्रचार को लेकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को एफआईआर दर्ज करने की दी तहरीर

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।मंगलवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने नि. महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के साथ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या नगर को तहरीर दिया।तहरीर के माध्यम से मांग किया कि विगत कुछ दिनों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या मंदिर परिसर में चढ़ावा आभूषण चोरी हुए जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरा आघात लगा है उक्त प्रकरण वर्तमान में देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है प्रकरण के संबंध में चढ़ावा चोरों को विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कराई गई है।देश के तमाम लोग तरह–तरह से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के संबंध में तमाम तरीके से पोस्ट कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी व संघ के लोगों को अपना नुकसान होता देख दिनांक 4 जुलाई से लगातार सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप, एक्स ,इंस्टाग्राम ,प्रियंका राय माने सरिया अखिलेश सिंह ग्लोबल भारत टीवी अमित भारद्वाज सांसद निशिकांत दुबे व जगत गुरु आचार्य पीठाधीश्वर परमहंस तपस्वी की छावनी रामघाट अयोध्या व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक साजिश करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विरुद्ध आधारहीन तथ्यहीन अनर्गल मनगढ़ंत वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लगातार कर रहे है।भ्रामक तथ्य जनता के बीच फैला रहे हैं राम मंदिर में हुए मंदिर घोटाले के आरोपी टिन्नू यादव ने विगत ढाई वर्ष से श्री अखिलेश यादव से 980 बार बात की है जबकि ये तथ्य पूर्ण गलत आधारहीन भ्रामक व कपोल कल्पित है उपरोक्त लोगों द्वारा जानबूझकर अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी के विरुद्ध अत्यंत भ्रामक आपत्तिजनक अशोभनीय टिप्पणी सोशल मीडिया एक्स पर की जा रही है जिससे अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी की मान प्रतिष्ठा जनता के बीच धूमिल हो रही है।जिसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार सांसद निशिकांत दुबे व जगतगुरु आचार्य पीठाधीश्वर परमहंस तपस्वी छावनी व कुछ अज्ञात लोग हैं सोशल मीडिया पर डाली गई उपरोक्त भ्रामक आपत्तिजनक पोस्टों की गहराई से पता लगाने से ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त पोस्ट अज्ञात लोगों द्वारा यूजर का नाम छुपा कर जालसाजी व कूट रचना के अपराधिक उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बदनाम व अपमानित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट अपलोड की गई है। इस मौके पर प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट ने बताया इस मौके पर महासचिव हामीद जाफर मीसम, राम अचल यादव, संजय सिंह,चौधरी चंद यादव, एडवोकेट शावेज जाफरी, एडवोकेट लाल बहादुर शुक्ला, शिवांशु तिवारी, अपर्णा जायसवाल, वीरेंद्र गौतम, राम अंजोर यादव देवा श्रीवास्तव, सचिन यादव रियाज अहमद,नूर बाबू, विद्या भूषण पासी, रोहित यादव भल्लू, कमलेश सोलंकी, वसी हैदर गुड्डू, सुरेंद्र यादव सुशील पांडे, इस्तिखार,इश्तियाक खान, शाहबाज लकी, अनस खान, रवि यादव जितेंद्र यादव, आदि लोग मौजूद रहे।

एसआईटी जांच में दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा - पंकज चौधरी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मंगलवार को अयोध्या पहुंचे।वह यहां एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने आए थे।उनके आगमन पर क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी,महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी ने उनका स्वागत किया।मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हाल के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजकल बिना पर्याप्त तथ्यों और साक्ष्यों के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों को अपना कार्य पूरी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ करने देना चाहिए।उन्होंने कहा कि संबंधित

प्रकरण की एसआईटी जांच जारी है और उत्तर प्रदेश सरकार पूरे मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है।सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है कि घटना की तह तक पहुंचकर सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है, वह निश्चित रूप से दुखद है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो,इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और निगरानी तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

पंकज चौधरी ने दोहराया कि एसआईटी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है।जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना और जनता का विश्वास बनाए रखना है।इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष से महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, अभिषेक मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने शिष्टाचार भेंट किया।

रामकथा पार्क के आसपास अवैध पार्किंग के आसपास हो रही है अवैध वसूली

अयोध्या।रामकथा पार्क के आसपास अवैध पार्किंग है। जिसको लेकर सनातन रक्षक संघ ने तीन लोगों पर आरोप लगाते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की है।इस पर अपर नगर आयुक्त बोले ने कहा कि इसकी जांच होंगी।संघ के अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नया घाट स्थित पार्किंग स्थल पर न तो रसीद दी जाती है और न ही डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। जबकि नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क प्रति घंटा 20 रुपये है,इसके बावजूद 10 से 15 मिनट वाहन खड़ा करने पर भी श्रद्धालुओं से 100 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। अपर नगर आयुक्तध्एसडीएम नागेंद्र कुमार ने ज्ञापन प्राप्त कर कहा कि मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी।यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।वही सनातन रक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो श्रद्धालुओं के हित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।संगठन का कहना है कि अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

करणी सेना ने पंकज कुमार सिंह को बनाया मवई ब्लॉक अध्यक्ष

अयोध्या। करणी सेना ने पंकज कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।उन्हें संगठन का मवई ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।यह नियुक्ति उनके सामाजिक और राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका को देखते हुए की गई है।संगठन द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में बताया गया है कि पंकज कुमार सिंह की समाज और राष्ट्रहित में सक्रियता तथा संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।करणी सेना ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में रुदौली क्षेत्र में संगठन और मजबूत होगा।पंकज कुमार सिंह अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ेंगे और इसके उद्देश्यों को जन–जन तक पहुंचाएंगे। वे सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।संगठन ने पंकज कुमार सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा जताई है कि वे करणी सैनिकों के साथ मिलकर संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस नियुक्ति से उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी है और विश्वास जताया है कि वे संगठन व समाज के हित में निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे।

स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी की मूर्ति का किया गया अनावरण'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मा0 मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह ने ग्राम बाबूपुर कचनारी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जननायक समाज के मार्गदर्शक स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी (पूर्व सांसद एवं विधायक) की मूर्ति का अनावरण किया तथा अपना घर वृद्धाश्रम का उद्घाटन भी किया। यह कार्यक्रम देशराज सेवा संस्थान उ0प्र0 के तत्वावधान मे आयोजित किया गया। इसके पूर्व उन्होंने वृद्धाश्रम परिसर मे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अन्तर्गत पौधरोपण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि अधिक से अधिक पौधे लगाये तथा उनका संरक्षण भी करे। उनके साथ उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने भी पौधरोपण किया। इस अवसर पर भव्य जनसभा भी आयोजित की गयी। जनसभा के दौरान मा0 रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जी का आनलाइन उद्बोधन प्रसारित किया गया। मा0 रक्षा मंत्री जी ने स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुये वृद्धाश्रम के उद्घाटन तथा प्रतिमा के अनावरण पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी। उन्होंने कहा कि धर्मगज सिंह का पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिये

समर्पित था, वह सच्चे अर्थ मे समाज के सेवक थे। उन्होंने कहा कि यह अत्यन्त हर्ष का विषय है, कि उनके समाज सेवा के सकंल्प को साकार करते हुये नई दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि वद्धाश्रम के रूप में सेवा स्थल विकसित करने का प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। अति विशिष्ट अतिथि एवं माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वर्गीय ठाकुर धर्मगज सिंह सोमवंशी जी का सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन सेवाभाव को समर्पित था। उनके विचार सदैव प्रेरणाश्रोत है, तथा समाज के लिये सदैव अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार देश की जनता के सर्वागीण विकास के लिये प्रयासरत है, तथा विकासशील से विकसित भारत बनाने की संकल्पना पर निरन्तर कार्य किये जा रहे है। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार बच्चों की पढाई, जन कल्याण के कार्यो, सभी के विकास हेतु सदैव तत्पर है तथा सुख–दुख में पूरी तरीके से सदैव सबके साथ है। उन्होंने कहा कि समाज मे बुजुर्गो को सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है। सनातन संस्कृति को मजबूत करने, समाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ करने के लिये भी उन्होंने प्रेरित किया। कार्यक्रम के भव्य आयोजन हेतु सभी आयोजकों को बधाई दी। कार्यक्रम में माननीय सांसद जय प्रकाश रावत, विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, विधायक श्याम प्रकाश आदि ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, वरिष्ठ नेता डॉ0 अशोक बाजपेई सहित सम्बन्धित अधिकारी, माननीय जन प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।

जिले मे मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत 13 स्कूली वाहनों का चालान व 6 वाहन सीज

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। बच्चों की सुरक्षित स्कूल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने जिले में शमिशनरू सेफ फ्यूचरश अभियान तेज कर दिया है। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यह विशेष अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस और परमिट की शत–प्रतिशत जांच सुनिश्चित करना है।अभियान का संचालन संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विश्वजीत प्रताप सिंह और संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय झा के निर्देशन में किया जा रहा है। इसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, यात्रीध्मालकर अधिकारी और मोटर यान निरीक्षक की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ आरपी सिंह के अनुसार प्रदेश में कई स्कूल वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र या बिना वैध परमिट के संचालित पाए गए हैं। ऐसे वाहन बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इसी को देखते हुए विशेष अभियान शुरू किया गया है।अभियान के तहत मंगलवार को जिंगल बेल स्कूल, अयोध्या में सड़क सुरक्षा और स्कूल वाहन सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और वाहन चालकों को सुरक्षित परिवहन के नियमों की जानकारी दी गई।डॉ सिंह के अनुसार 1 जुलाई से 7 जुलाई 2026 के बीच अभियान के दौरान 13 स्कूली वाहनों का चालान किया गया, जबकि 6 वाहनों को बंद करने की कार्रवाई की गई। अब अभियान के दूसरे चरण में 8, 9 और 10 जुलाई 2026 को स्कूली वाहनों के साथ–साथ अनधिकृत यात्री वाहनों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा।परिवहन विभाग ने सभी स्कूल संचालकों और वाहन मालिकों से फिटनेस, परमिट और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट रखने की अपील की है।

ओवरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत

अयोध्या। दलसराय ओवरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत, रुदौली कोतवाली क्षेत्र के दलसराय ओवरब्रिज के पास मंगलवार सुबह एक 20 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अरुण कुमार रावत (20) निवासी रहीमगंज मजरा देवकली का पुरवा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके

पर पहुंची।ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।घटना के संबंध में सीओ रुदौली अरविंद सोनकर तथा प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही ने संयुक्त रुप से बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया कि उक्त युवक के पत्नी के साथ कुछ विवाद हुआ था,पत्नी से गुस्से में आकर उक्त युवक रेलवे ट्रैक के पास आकर शारदा सहायक नदी के समीप खड़ा हो गया और इस बीच वहां से ट्रेन गुजरी और उसकी चपेट में आकर युवक नहर में गिर गया जिसके चलते मौत हो गई।

सपा मंत्री तेज नारायण पाण्डेय पवन ने दी तहरीर

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।मंगलवार को सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों पर एफआईआर की मांग की।आरोप है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे,जगतगुरु परमहंस आचार्य व अन्य ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर 980 बार बात करने का झूठा आरोप लगाकर सपा प्रमुख को बदनाम किया।उन्होंने दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की।इस मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पाण्डेय पवन के अलावा सपा के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पति की पहले ही हो चुकी है मौत, अब दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया– हादसे में गई जान

गोरखपुर, (संवाददाता)। सलेमपुर नगर पंचायत में सोमवार सुबह सड़क किनारे टहल रही एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। देवरिया–सलेमपुर मुख्य मार्ग पर स्टेट बैंक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने दूध लदे वाहन में पीछे से टक्कर मार दी। दुग्ध वाहन पलट गया और उसकी चपेट में आकर महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सोमवार की सुबह सलेमपुर मुख्य मार्ग पर स्टेट बैंक की शाखा

के पास हुई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दुग्ध वाहन में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुग्ध वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क किनारे टहल रही महिला को अपनी चपेट में ले लिया। मृतका की पहचान बबीता (35) पत्नी स्वर्गीय विपिन बिहारी, निवासी ग्राम अहिरौली लाला के रूप में हुई है। बबीता सलेमपुर कस्बे में ब्यूटी पार्लर चलाकर अपने परिवार का पालन–पोषण करती थीं। उनके पति का पहले ही निधन हो चुका है। उनके परिवार में 18 वर्षीय बेटी स्नेहा कुमारी और 16 वर्षीय बेटा आदित्य कुमार हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक सोहनाग मोड़ के पास वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सलेमपुर कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।

आरपीएफ कर्मियों द्वारा कैंट रेलवे स्टेशन पर जागरुता अभियान चलाकर रेल यात्रियों को किया जागरूक

अयोध्या। प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही के नेतृत्व में तथा उप निरीक्षक रचना यादव की सक्रिय निगरानी में पिछले दिनों से कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।इस मौके आरपीएफ उप निरीक्षक रचना यादव अपनी टीम के साथ स्टेशन परिसर,सभी प्लेटफार्मों एवं ट्रेनों में यात्रियों को अनावश्यक चेन पुलिंग से होने वाले नुकसान,सामान चोरी से बचाव,जहरखुरानी गिरोहों की गतिविधियों तथा ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने के खतरों के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई दी।बताते चले कि आगामी श्रावण मास और रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ को देखते हुये यह अभियान सुरक्षा की दृष्टि से चलाया जा रहा है।इस मौके पर सुरक्षा कर्मी यात्रियों को यह भी समझा रहे है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस वस्तु अथवा आपात स्थिति की सूचना तत्काल रेलवे हेल्पलाइन एवं आरपीएफ को दें। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कैंट

रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही तथा उप निरीक्षक रचना यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि रेल यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक किया जा रहा है,वही स्टेशन परिसर के सभी प्लेटफॉर्मों,प्रतीक्षालय, रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया,आरक्षण केंद्रों तथा ट्रेनों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार चलेगा।

रेनबो वाटर पार्क के स्टाफ पर मारपीट और मोबाइल तोड़ने का आरोप

गोरखपुर, (संवाददाता)। पीड़िता मुस्कान सोनकर, निवासी बशारतपुर, थाना शाहपुर ने तहरीर देकर बताया कि वह रविवार को अपने परिवार के साथ रेनबो वाटर पार्क चौरीचौरा घूमने गईं थीं। आरोप है कि इसी दौरान वाटर पार्क के कुछ कर्मी नशे की हालत में उनके परिवार के साथ बदतमीजी करने लगे। विरोध करने पर स्टाफ ने गाली–गलौज करते हुए लाठी–डंडों से हमला कर दिया।

87 से अधिक ब्लैक बेल्ट प्रतिभागियों को मिला प्रशिक्षण

गोरखपुर, (संवाददाता)। शहर के पार्क रोड स्थित एक होटल में आयोजित दो दिवसीय 55वें क्वालिफाइंग इंटरनेशनल अंपायर कोर्स का रविवार को समापन हो गया। कोर्स में 87 से अधिक ब्लैक बेल्ट प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा श्रीलंका, नेपाल और मलयेशिया से आए खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों ने भी सहभागिता की। दो दिवसीय कोर्स में प्रतिभागियों को अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग के नवीनतम नियमों और तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूरा करने वाले ब्लैक बेल्ट प्रतिभागियों को अंपायर कोर्स का प्रमाण–पत्र भी प्रदान किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय आयोजन युवाओं को विश्वस्तरीय अवसर उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देते हैं। कोर्स का संचालन इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन की अंपायर कमेटी के चेयरमैन अर्जेंटीना के ग्रैंड मास्टर अबलाडो राफेल बेनजेक्विन ने किया।

श्वेता वर्मा बनी अयोध्या जनपद के ग्राम्य विकास अभिकरण की परियोजना निदेशक

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। श्वेता वर्मा अयोध्या जनपद के ग्राम्य विकास अभिकरण की परियोजना निदेशक बनी।मालूम हो कि श्वेता वर्मा इसके पूर्व संत कबीर नगर जनपद में खण्ड विकास अधिकारी के रूप में तैनात रही है।

पदोन्नति के बाद उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।जबकि अभी तक अयोध्या जनपद में परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे गिरीश पाठक को संयुक्त आयुक्त के पदोन्नति के पश्चात कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश से संबद्ध कर दिया गया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।